



अहिंसा और सत्य ये दोनों हमारे जीवन विकास के पहलू हैं।

nonviolence and truth both these are aspects of development in our life.

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 284 ● वर्ष : 12 ● रायपुर, शनिवार 03 मई 2025 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रुपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन

मुख्यमंत्री साय आज पंजीयन (रजिस्ट्री) विभाग की 10 नवीन सुविधाओं का करेंगे शुभारंभ



मेसर्स रेक बैंक के एआई डाटा सेंटर का होगा शिलान्यास

रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 3 मई की नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पंजीयन (रजिस्ट्री) विभाग की नवाचार आधारित 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ और मेसर्स रेक बैंक द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक एआई डाटा सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। यह कार्यक्रम राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और आप नागरिकों को पारदर्शी, सरल तथा ताजीकी सुलभ सेवाएं प्रदान करने की दिशा में बहुद महत्वपूर्ण कदम होगा।

पंजीयन विभाग द्वारा आप नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और दस्तावेजों की सुरक्षा के दृश्य से पंजीयन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया गया है। इन सुविधाओं में आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्वें एवं डाउनलोड, कैशलेस भुगतान, डिजिटलर्क, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, घर बैठे रजिस्ट्री, डिजिटल्यूमेंट, स्वतः नामांतरण जैसी तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं से रजिस्ट्री प्रक्रिया, पेपरलेस सुरक्षित और नागरिकों के लिए सहज हो सकेंगी। अब आप नागरिक रजिस्ट्री से जुड़ी सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय, श्रम और धन की बचत होगी। कार्यक्रम में सुख्यमंत्री श्री साय द्वारा जिस एआई डाटा सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा, वह नवा रायपुर के सेक्टर 22 में विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 5 मेगावाट क्षमता का यह केंद्र पर्यावरण संरक्षण मानकों का पालन करते हुए सौंफ ऊर्जा आधारित होगा तथा भविष्य में इसकी क्षमता 150 मेगावाट तक विस्तार की जा सकेगी। लगभग 1000 करोड़ के निवेश वाली इस परियोजना से 500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह इकाई राज्य की औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30 के तहत एक यूनिट के रूप में विकसित होगी। इसके साथ ही राज्य में आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेवाओं से जुड़े एक नए इको-सिस्टम के विकास की नींव रखी जाएगी।

विज्ञिनजाम बंदरगाह का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन

मंच पर दिखे थर्लर, प्रधानमंत्री बोले- इस कार्यक्रम से कई लोगों की उड़ी नींद

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8, 900 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 'विज्ञिनजाम इंटरेशनल डीपावटा मल्टीपर्ज सीपोर्ट' राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिराई विजयन और कागेस सारांसद शिंग थर्लर भी जून रहे। केरल सरकार की राज्यालय की परियोजना को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोर्पोरेशन जोन लिमिटेड (एपीएसईजड) द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है।

विज्ञिनजाम बंदरगाह का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक तरफ विश्वाल समुद्र है, जिसमें अनेक अवसर हैं और दूसरी तरफ प्रकृति की सुंदरता है, इन दोनों के बीच यह 'विज्ञिनजाम अंतर्राष्ट्रीय गहरे नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस नई दिल्ली (आरएनएस)। नेशनल हेराल्ड से जुड़े कविय मनी लॉन्डिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कागेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जारी किया है। अदालत का यह कदम प्रवर्तन निवेशलय (ईडी) द्वारा मामले में दायर किए गए आरोपपत्र (चार्जरीट) के बाद आया है, जिसमें दोनों प्रमुख कागेस नेताओं को आरोपित बनाया गया है। इडी ने यह आरोपपत्र दिल्ली को विस्तार देने विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह कार्यशाला बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप बेहद प्रासंगिक है। भारत एक युवा देश है और यह युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण मिले, तो हम 'विकसित भारत' के लक्ष्य को जेजी से हासिल कर सकते हैं। इस मार्केपर राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए।



पानी वाला बहुदेशीय बंदरगाह' है, जो एक युग के विकास का प्रतीक है। इस बंदरगाह का निर्माण 8, 800 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और निकट भविष्य में इसके ट्रांसशिपमेंट हब की क्षमता तीन गुनी हो जाएगी। इसे बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है। अब तक, भारत की 75 प्रतिशत ट्रांसशिपमेंट गतिविधियां विदेशी बंदरगाहों पर संचालित की जा रही हैं। उसमें केरल का बड़ा योगदान था। उसमें बाली वाली वात थी, इसकी प्रभावशाली समुद्री क्षमताएं और इसके बंदरगाह शहरों में संपर्क अधिक गतिविधियां। केरल ने इस सफलता में विशेष भूमिका निर्वाही। भारत सरकार ने, राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है।

जाती थीं, जिसके परिणामस्वरूप देश को राज्यका बड़ा नुकसान होता था। हालांकि यह बदलने वाला है। पहले विदेशों में खर्च किए जाने वाले धन को अब थरेल विकास में लगाया जाएगा, जिससे विज्ञिनजाम और केरल के लोगों के लिए नए अधिक अवसर पैदा होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि देश की संपर्क सीधे अपने नागरिकों को लाभान्वित करे।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि गुलामी से फले हमारे भारत ने हजारों वर्षों से समुद्रिदेशी बदले हुए। एक समय वैश्विकी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उसमें केरल का बड़ा योगदान था। उसमें बाली वात थी, इसकी प्रभावशाली समुद्री क्षमताएं और इसके बंदरगाह शहरों में संपर्क अधिक गतिविधियां। उसमें केरल ने इस सफलता में विशेष भूमिका निर्वाही। भारत सरकार ने, राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। कुछ सार्वजनिक ब्रांसर एवं अमेरिका के अनुसार, खसरा तब खत्म माना जाता है जब कीसी देश में कम से कम 12 महीने तक मजबूत निगरानी प्रणाली के तहत स्थानीय स्तर पर इसका प्रसार न हो।

टेक्सास में 'खसरे' ने मचाया कहर, एक साथ 700 से अधिक लोग बीमार प्रशासन की चिंता बढ़ी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और महामारी वैज्ञानिकों ने इस अप्रैल के साल से अधिक समय तक चल सकता है, जिससे अमेरिका का खसरा-मुक्त दर्जा खत्म हो जाएगा। एजेंसी सिन्हुआ प्रकोप ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। मीडिया ने बताया कि पश्चिम टेक्सास में खसरे के रोगियों अधियांश के बाद यह उपचार हसिल करने की थी, जिसके बाद यह अनुसार, जनवरी के अंत में शुरू हुए खसरे से टेक्सास में 700 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक समय वैश्विकी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उसमें केरल का बड़ा योगदान था। उसमें बाली वात थी, इसकी प्रभावशाली समुद्री क्षमताएं और इसके बंदरगाह शहरों में संपर्क अधिक गतिविधियां। उसमें केरल ने इस सफलता में विशेष भूमिका निर्वाही। भारत सरकार ने, राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है।

युवा शक्ति से होगा 'विकसित भारत' का निर्माण : मुख्यमंत्री साय

छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को लेकर किए 4 महत्वपूर्ण एमओयू खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

मुख्यमंत्री ने कौशल, रोजगार और आजीविका पर नीति-आयोग की कार्यशाला का किया शुभारंभ रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला के राज्य समर्थन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास, रोजगार और आरोपित विकास के लिए एक अदालत की एक अदालत ने आरोपपत्र दिल्ली को विरोध शायद किया है। अदालत का यह कदम प्रवर्तन निवेशलय (ईडी) द्वारा मामले में दायर किए गए आरोपपत्र (चार्जरीट) के बाद आया है, जिसमें दोनों प्रमुख कागेस नेताओं को आरोपित बनाया गया है। इडी ने यह आरोपपत्र दिल्ली को राज्य एवं नीति-आयोग की कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह कार्यशाला बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप बेहद प्रासंगिक है। भारत एक युवा देश है और यह युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण मिले, तो हम 'विकसित भारत' के लक्ष्य को जेजी से हासिल कर सकते हैं। इस मार्केपर राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए।



मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि 2047 तक छत्तीसग

यथार्थ को पलटने की कोशिश.....

आलेख

**किसी को अंदाजा नहीं है
कि क्या बड़ा होने वाला है**

अजोत द्विवेदी

जम्पू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में मंगलवार, 22 अप्रैल को हुए नरसंहार के बाद भारत की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया बुधवार, 23 अप्रैल की देर शाम को आई, जब सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीएस की बैठक में पांच बड़े फैसले किए गए। यह एक त्वरित और कूटनीतिक प्रतिक्रिया है, जिस पर नागरिकों के एक बड़े समूह को निराशा हुई है। उनका कहना है कि पहलगाम जैसी बड़ी घटना के बाद भारत की प्रतिक्रिया इतनी मुलायम नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत को तत्काल पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। लोग सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

सोशल मीडिया 'देशभक्तों' की खून खौलने वाली बातों से भरा है। खून के बदले खून की मांग की जा रही है। जाहिर है ऐसी घटनाओं के बाद आम लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है और सरकारें बड़े सामरिक फैसले आम लोगों की प्रतिक्रिया के हिसाब से नहीं करती हैं। फिर भी यह सवाल तो है ही कि पहलगाम के बाद क्या रास्ता है? जरूरी सुधारों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक पहल और योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, बढ़ावस्था सुरक्षा, वित्तीय समावेशन,

हां। कर मा वह सवाल तो हो गया कि पहलगाम के बाद क्या रास्ता है? क्या भारत सरकार पहलगाम की घटना को आगे के बड़े खतरे का संकेत समझ कर ऐसी कार्रवाई करगी, जो इससे पहले नहीं हुई हो या सरकार की प्रतिक्रिया वैसी ही होगी, जैसी उरी के बाद हुई, बालाकोट के बाद हुई या पुलवामा के बाद हुई? कह सकते हैं कि भारत ने एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? क्या आतंकवाद का नेटवर्क ध्वस्त हो गया? क्या सीमा पार के सारे आतंकवादी लॉन्च पैड नष्ट हो गए? क्या आतंकवादी संगठनों के सरगना मारे गए? ऐसा कुछ नहीं हुआ।

उससे या अपारदर्शी संतुष्ट नहीं हो सकते से ज्ञान संसाधनों से सशक्तिकरण, वृद्धिवस्था सुकृति, वित्तीय समवर्षण, अंतिम व्यक्ति तक परिवहन व संचार संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के समर्पित प्रयासों के तहत सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सम्मानजनक और निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कुछ ही सप्ताह पहले रिजिजू ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सम्मानजनक व्यवस्थाओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने और इसे सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था। उस विदेशी दौरी की वजह से उसके दौरान उसके दूषितकाण में बदलाव ह, सरकार का राजनीति से जनता के सशक्तिकरण की ओर कदम है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारतीय हज समिति के माध्यम से मुख्य कोटे के तहत चालू वर्ष में 122,518 तीर्थयात्रियों की व्यवस्था का प्रबंधन कर रहा है। सऊदी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना बहुत जरूरी है। लेकिन राजनीतिक प्रभाव खोने के डर से सरकार के संतुष्ट-अधिकारी समाजी विदेशी दौरी को उसके दौरान भारत का मुस्लिम समुदाय ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। इस अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम संपत्तियों को जो करना है। ये समूह तथ्यों और आंकड़ों से कतराते हुए वक्फ संपत्ति की आय में लगातार गिरावट न संबोधित करने में विफल रहे हैं, या स्वीकार करना न चाहते कि वक्फ संपत्ति का क्षेत्रफल 2013 के 17 लाख एकड़ से बढ़ कर आज 39 लाख एकड़ हो गया भारत का मुस्लिम समुदाय ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एक रास्ता अपारदर्शी नेतृत्व और पुरानी व्यवस्था की ओर जाना है।

देश में विकास और कषि-पशापलन हाँच

यह अलग बात है कि सरकार लगातार यह नैरेटिव बनाने का से आंशिक सफलता हासिल हुई।

A photograph showing a large herd of brown cows standing in a dry, open field. The cows are of various sizes, suggesting a mix of adults and calves. They are looking towards the camera or slightly to the side. The background is a simple, light-colored sky and some sparse vegetation.

जीएसटी का रास्ता आसान बनाने की जरूरत

मधुरेंद्र सिन्हा

इस समय टैक्स के चार स्लैब हैं- 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत। इन्हें घटाकर तीन स्लैब करना चाहिए। इन दरों को तरक्की संगत बनाने से वैधानिक मामले कम हो जाएंगे। साथ ही, जीएसटी की रिटर्न प्रणाली और इनपुट टैक्स क्रेडिट नीति में भी बदलाव की जरूरत है। जीएसटी लागू हुए 8 वर्ष हो गए, लेकिन इसके नियमों में हर महीने बदलाव होते रहते हैं जिससे व्यापारियों में भ्रम पैदा होता है। यह तो थी ग्राहकों और कारोबारियों की परेशानी। लेकिन सरकार की शिकायत है कि अभी भी जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। कई राज्यों में भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से चोरी हो रही है देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद जो सबसे बड़ा सुधार हुआ, वह था 'वन नेशन वन टैक्स' का फैसला। इसके तहत ही जीएसटी की नींव रखी गई। कई सरकारों से गुजरत हुआ यह अंत में जीएसटी के रूप में पहली जुलाई 2017 को संसद में पारित हुआ और इसे टैक्स बसूली और कारोबारियों को राहत देने की दिशा में एक गेम चेंजर माना गया। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर बहुत काम किया और उम्मीद जताई कि यह टैक्स भरने में एक सुगम व्यवस्था बन जाएगा। लेकिन शुरुआत बहुत बुरी हुई और पहले तो इसका बेबासाइट बार-बार क्रैश करने लगा और पिछे बहुत से कॉलम भी आसानी से भरे नहीं जा रहे थे। इन तकनीकी समस्याओं से जूझते हुए भी इस सुधार को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इसमें तरह-तरह की अड़चनें आने लगीं जिसका अंत अब तक होता नहीं दिख रहा है। कारोबारियों को बताया गया था कि यह आसान व्यवस्था होगी और उनके लिए टैक्स भरना पहले से भी आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई तरह की समस्याएं आती रहीं और कई तरह की विसंगतियां भी। लेकिन पूर्ण समाधान होता नहीं दिख रहा है। दरअसल जीएसटी को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी और वह अभी भी इसका काम देखती है। भारत सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत यह नहीं है, सिवा इसके कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता करती हैं। उन्हें अपने बूते किसी भी तरह का फैसला करने का अधिकार नहीं है। वहां जो

लोकतंत्र में हर्ष रंजन

वर्ष 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समावेश, सम्मान और सभी के लिए विकास के मंत्र के साथ शासन को गति दी है। अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति उनके प्रशासन की नीतियां इस दर्शन को केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी कार्य में भी रेखांकित करती हैं। लेकिन मोदी सरकार भारत के अल्पसंख्यक समुदायों विशेष रूप से मुसलमानों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करती है तो कुछ निहित स्वार्थी तत्व जनता को गुमराह करने और बहुत जरूरी सुधारों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने समाज के सभी वर्गों के उद्धारण के लिए कई ऐतिहासिक पहल और योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, वृद्धावस्था सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, अंतिम व्यक्ति तक परिवहन व संचार संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष केंद्रित प्रयास शामिल हैं। पोषण अभियान, पीएम आवास योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम मुद्रा योजना और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रम इस समावेशी मॉडल के उदाहरण हैं, जो सार्वभौमिक और न्यायसंगत व्यवस्था के माध्यम से अल्पसंख्यकों सहित उन लोगों को समग्र सहायता प्रदान करते हैं, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वक्फ

देश में वि

रामलाल पाठक

किसान उन्नत नस्ल के बैल पालने के बहुत शौकीन थे। कई किसान तो हरियाणा एवं पंजाब से बैल पालने को लाते थे। अनेक स्थानों पर पशु मंडियां लगती थीं देश एवं प्रदेश की खुशहाली के लिए कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में पिंड से विकास की बयार बहेगी तथा बेरोजगारी को दूर करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा यदि सरकार इसके लिए अनुदान देती है। नकद राशि मिलने से बेरोजगार युवा खेतीबाड़ी करने के साथ ही पशु पालने में रुचि लेंगे। अन्यथा ग्रामीण क्षेत्र में यह स्थिति हो गई है कि लोगों को सब्जियां या दूध आदि का वितरण शहरों से हो रहा है। एक समय था जब ताजा शुद्ध दूध गांव-गांव से इकट्ठा करके शहर ले जाया जाता था। फल व सब्जियां भी गांव से ही जाती थीं। शहरवासी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को गुणवत्ता से परिपूर्ण मानते हुए बड़े चाव से उनका उपयोग करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। गांव के लोग भी शहर से लाए उत्पादों का बड़े चाव से सेवन कर रहे हैं। उसमें यह नहीं देख रहे हैं कि उनकी रसोई तक



भी फैसले होते हैं, वे सभी बहुमत से होते हैं, यानी सभी राज्यों के चुने प्रतिनिधियों जो सामान्य रूप से वित्त मंत्री होते हैं। यह इस कार्डिसिल का लोकान्त्रिक स्वरूप जताता है, लेकिन यह कई बड़े फैसले न ले पाने का कारण भी बनता है। वित्त मंत्री की बहुत इच्छा रही है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए, ताकि इसके दाम भी पूरे देश में लगभग एक समान हों, लेकिन कई सदस्य इसे होने नहीं दे रहे हैं। वे अपने राज्य के हित में चलते हुए ऐसा नहीं होने देते। जब भी किसी राज्य को अपना राजस्व बढ़ाना होता है, वह तुरंत ही पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक, जहां इनकी कीमतें सबसे ज्यादा हैं। अगर इस पर जीएसटी लगा होता तो ऐसा संभव नहीं था। यह तो हुई जनता की परेशानी। अब आते हैं कारोबारियों-व्यापारियों पर जो अब तक जीएसटी भुगतान में सहज नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कई तरह की विसंगतियां हैं, मसलन दो तरह के सामान जो मिलकर एक उत्पाद होते हैं, उन पर अलग-अलग टैक्स दरें हैं। यह कारोबारी के लिए एक परेशानी है। अगर हम भारत के एक पॉपुलर स्ट्रैक्ट बन मस्का को देखें तो पाएंगे कि बन पर टैक्स की दर अलग है और मस्का यानी मक्खन पर अलग। अब व्यापारी किस दर से टैक्स लेगा? रेस्तरां में रोटी पर कम टैक्स है तो परांठे पर ज्यादा। बिना ऐसी वाले रेस्तरां के लिए अलग दर है तो ऐसी वाले के लिए अलग। खुले सामान पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन पैकेट में आते ही उस पर टैक्स लगेगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो जीएसटी की विसंगतियां बताते हैं। इसके अलावा कई सेवाओं पर 18 फीसदी का भारी भरकम टैक्स भी है। एक ओर तो सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करती है, तो दूसरी ओर कार्डिसिल ने हेल्पिंग इंश्यारेंस पर 18 फीसदी जीएसटी लगा रखा है। व्यापारियों का कहना है कि दरों में विसंगति न हो और उन्हें तार्किक बनाया जाए। उनकी यह भी शिकायत है कि वे पूरे माह जीएसटी रिटर्न भरने में लगे रहते हैं, नहीं तो लाखों की देनदारी का नोटिस आ जाता है। रेस्तरां के एसी या नॉन एसी होने से जीएसटी कैसे घट-बढ़ सकता है जबकि आज देश में निम्न आय वर्ग के लोग भी भीषण गर्मी की मार से बचने के लिए अपने घरों में एसी लगाते हैं। इस समय टैक्स के चार स्लैब हैं- 5, 12, 18 और 28 फीसदी। इन्हें घटाकर तीन स्लैब करना चाहिए। इन दरों को तर्कसंगत बनाने से वैधानिक मामले कम हो जाएंगे। साथ ही, जीएसटी की रिटर्न प्रणाली और इनपुट टैक्स क्रेडिट नीति में भी बदलाव की जरूरत है। जीएसटी लागू हुए 8 वर्ष हो गए, लेकिन इसके नियमों में हर महीने बदलाव होते रहते हैं जिससे व्यापारियों में भ्रम पैदा होता है। यह तो थी ग्राहकों और कारोबारियों की परेशानी। लेकिन सरकार की शिकायत है कि अभी भी जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। कई राज्यों में भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से चोरी हो रही है। साल 2022-23 में देश में दो लाख करोड़ ऐसे में कारोबारियों को अभी भी इसे पूरी तरह समझने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को दूर करने के लिए बाजार आज कई तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके ज़रूरी कारोबारी आसानी से अपना जीएसटी रिटर्न समय भर सकते हैं। जीएसटी के नियम समझने के लिए अकांटिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए और रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास कंप्यूटर का ज़रूरी होना चाहिए, जो कि छोटे कारोबारियों में कम व्यावेशी के लिए अपरिवारियों को सारा काम खुद करना होता है। इसके अलावा नियम अगर आसान हों तो कोई भी कारोबारी बिना किसी अकांटिंग विज्ञान कारी के जीएसटी को समझ सकती है। इसके रिटर्न फाइलिंग भी आसान हो सकती है। जैसे फाइल इनवॉयस लैबल डिटेल की जगह पार्टी वाइज समर्पित अपलोड की जा सके। साथ ही एचएसएन कोड द्वारा बहुत ज्यादा जोर नहीं होना चाहिए। वहीं रिपोर्ट एचएसएन के अनुसार न होकर टैक्स रेट के अनुसार ही हो सकती है। इसके अलावा आरसीएम को अनुसार बनाया जा सकता है जैसा कि यूईई समर्पित कुछ देशों में है। अगर इस तरह के बदलाव हो सकता है तो निश्चित तौर पर जीएसटी देश के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसके साथ ही छोटे अधिकारियों के रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ाना और इसमें उनकी सहायता के लिए प्रोफेशनल की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है।

लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना बहुत ज़रूरी

हष रजन

वर्ष 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद संप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समावेश, सम्मान और सभी के लिए विकास के मंत्र के साथ शासन को गति दी है। अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति उनके प्रशासन की नीतियां इस दर्शन को केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी कार्य में भी रेखांकित करती हैं। लेकिन मोदी सरकार भारत के अल्पसंख्यक समुदायों विशेष रूप से मुसलमानों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करती है तो कुछ निहित स्वार्थी तत्व जनता को गुमराह करने और बहुत जरूरी सुधारों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक पहल और योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, वृद्धावस्था सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, अंतिम व्यक्ति तक परिवहन व संचार संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष केंद्रित प्रयास शामिल हैं। पोषण अभियान, पीएम आवास योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम मुद्रा योजना और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रम इस समावेशी मॉडल के उदाहरण हैं, जो सार्वभौमिक और न्यायसंगत व्यवस्था के माध्यम से अल्पसंख्यकों सहित उन लोगों को समग्र सहायता प्रदान करते हैं, जिनमें सार्वभौमिक अधिकार असमर्पित हैं। उन्हें

लाभत था। मुस्लिम समुदाय के कल्याण के उद्देश्य के लिए बनाई गई वक्फ संपत्तियों में दशकों से जवाबदेही की कमी और अपारदर्शी प्रबंधन मौजूद है। नये संशोधन नियामक निरीक्षण, निष्पक्षता और पारदर्शिता लाकर इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य से, इसने उन लोगों के सुनियोजित विरोध को जन्म दिया है, जो कभी यथास्थिति से लाभान्वित होते थे। उनकी बेचैनी समझी जा सकती है; लेकिन सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि विपक्ष किस तरह सांप्रदायिक बयानबाजी में उलझा रहता है और सरकार द्वारा जनता के हित में किए जा रहे ठोस प्रयासों को आसानी से नजरअंदाज कर देता है। सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को समझने के लिए 2025 की आगामी हज यात्रा के लिए सरकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण को देखना ही काफी है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्श नेतृत्व और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के समर्पित प्रयासों के तहत सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सम्मानजनक और निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कुछ ही सप्ताह पहले रिजिजू ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सम्मानजनक व्यवस्थाओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने और इसे सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। यह विस्तार सर्वत्र है; यह सेवी समाज का आध्यात्मिक महत्व के लिए इस स्तर की भागीदारी और देखभाल का प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, पारदर्शिता और समान अवसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हज 2023 से 500 सीटों के विवेकाधीन हज कोटे को समाप्त कर दिया है। यह कोटा, जो पहले मंत्रियों, राजनयिकों और नौकरशाहों सहित वीआईपी के लिए आरक्षित था, अवसर पवित्र तीर्थयात्रा प्रक्रिया में विशेषाधिकार और पक्षपात की प्रतीक थी। इसे समाप्त करके, सरकार ने कड़ा संदेश दिया है- आम मुसलमानों का कल्याण और अधिकार मायने रखते हैं। यह सुधार केवल प्रशासनिक नहीं है। यह दृष्टिकोण में बदलाव है, संरक्षण की राजनीति से जनता के सशक्तिकरण की ओर कदम है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारतीय हज समिति के माध्यम से मुख्य कोटे के तहत चालू वर्ष में 122,518 तीर्थयात्रियों की व्यवस्था का प्रबंधन कर रहा है। सऊदी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना बहुत जरूरी है। लेकिन राजनीतिक प्रभाव खोने के दूर से सरकार के संतुलित-आधिकारी विचार निर्देशों ने उसमें दो बड़े बदलाव ले लाये हैं। प्रातानाधित्व करने का दावा आलाचक करते हुए समय आ गया है कि चर्चा को राजनीतिक दिखाने से अलग करके जन कल्याण की ओर मोड़ दिया जाए। हमें भ्रामक आख्यानों को वास्तविक प्रगति हावी नहीं होने देना चाहिए। वक्फ सुधार कोई हमरी नहीं है, बल्कि उत्तरायन है। पंद्रह-सूत्री कार्यक्रम ने पुनर्मूल्यांकन उपेक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि तरीका के सुधार से संबंधित है। सरकार की बर्जटाएं, विकसित भारत तथा विकसित समावेशी और दूरदर्शी भारत के दृष्टिकोण के प्रष्ट और निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नवीनीति वक्फ अधिनियम किसी के राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बनाया गया है; इसका उद्देश्य अम मुसलमानों के व्यापक हितों की सेवा करना है। परन्तु भी, कुछ चुनिंदा समूह गलत धारणा फैला रहे हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम संपत्तियों को जनता के संबंधित करना है। ये समूह तथ्यों और आंकड़ों से कतरता हैं और वे वक्फ संपत्ति की आय में लगातार गिरावट देते हैं। संबंधित करने में विफल रहे हैं, या स्वीकार करना नहीं चाहते कि वक्फ संपत्ति का क्षेत्रफल 2013 के 17 लाख एकड़ से बढ़ कर आज 39 लाख एकड़ हो गया भारत का मुस्लिम समुदाय ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एक रास्ता अपारदर्शी नेतृत्व और पुरानी व्यवस्था की दूसरी ओर लाया जाना है।

देश में विकास और कृषि-पशुपालन ढांचा

रामलाल पाठक

A photograph showing a group of several brown cows standing in a dry, open field. The cows are of different sizes, suggesting a mix of adults and younger ones. They are looking towards the camera or slightly off to the side. The background is a simple, dry landscape with no other structures or people visible.

किसान उत्तर नस्ल के बैल पालने के बहुत शौकीन थे। कई किसान तो हरियाणा एवं पंजाब से बैल पालने को लाते थे। अनेक स्थानों पर पशु मंडियां लगती थी देश एवं प्रदेश की खुशहाली के लिए कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में पिछ से विकास की बयार बहेही तथा बेरोजगारी को दूर करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा यदि सरकार इसके लिए अनुदान देती है। नकद राशि मिलने से बेरोजगार युवा खेतीबाड़ी करने के साथ ही पशु पालने में रुचि लेंगे। अन्यथा ग्रामीण क्षेत्र में यह स्थिति हो गई है कि लोगों को सब्जियां या दूध आदि का वितरण शहरों से हो रहा है। एक समय था जब ताजा शुद्ध दूध गांव-गांव से इकट्ठा करके शहर ले जाया जाता था। फल व सब्जियां भी गांव से ही जाती थी। शहरवासी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को गुणवत्ता से परिपूर्ण मानते हुए बड़े चाव से उनका उपयोग करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बिपरीत हो गई हैं। गांव के लोग भी शहर से लाए उत्पादों का बड़े चाव से सेवन कर रहे हैं। उसमें यह नहीं देख रहे हैं कि उनकी रसोई तक एक समय था जब ग्रामाण स्तर पर कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय एक दूसरे के पूरक थे। पहले पशुओं, विशेषकर बैलों के बिना खेतीबाड़ी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब तोग इस काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे भी गांव में अब खेतीबाड़ी करना बहुत मुश्किल हो गया है। उपजाऊ जमीन विरान पड़ गई है। जहां खाली जगह है वहां जहरीला फुलण घास व कटीली झाड़ियों के जंगल खड़े हो गए हैं। घासनियों में भी जहरीली घास फैल गई है। कुल मिलाकर जमीन बंजर हो गई है। अब गांव में जो इक्का-दुक्का परिवार खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उन्हें जितना खर्च करना पड़ता है, उस हिसाब से फसल नहीं हो रही है। अन्य पशु अब लावारिस होकर सड़कों पर भटक रहे हैं। पहले शहर में ही इक्का-दुक्का लावारिस पशु नजर आते थे, लेकिन अब गांव-गांव तक लावारिस पशुओं के झुंड घूमते देखे जा सकते हैं। ग्रामीणों को लग रहा है कि अब खेतीबाड़ी एवं पशुपालन बहुत ही घाटे की सौदा हो गया है। इन दोनों व्यवसायों में खर्च के मुताबिक आय नहीं हो रही है। सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हलांकि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिए जाने के बाद कृषि क्षेत्र में मामूली सुधार हुआ है। लेकिन इसके लिए और अधिक धनराशि की जरूरत है। यदि सरकार बैल पालने के लिए हर महीने प्रति जोड़ी 1500, गाय या भैंस पालने के लिए 750 रुपए मासिक तथा भेड़ व बकरी पालन के लिए 250 रुपए अनुदान दे, तभी कृषि के साथ ही पशुपालन व्यवसाय पिछ से पनप पाएगा। इससे एक तो बेसहारा पशुओं की समस्या का हल होगा तथा दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की तरह कृषि उपज भी बढ़ेगी। ग्रामीणों को अपने गांवों में अच्छा अनाज, शुद्ध दूध-दही व धी के साथ ही फल व सब्जियां उपलब्ध होंगी। ग्रामीणों को अपने घरों में ही रोजगार उपलब्ध होगा। इससे हिमाचल सरकार को दूध व प्रस्तावित गोबर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले करीब चार दशकों से व्यवसाय म जबरदस्त पारावट आइ ह समय था जब ग्रामीणों में यह कहाना 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निविद चावाकरे गवर' प्रचलित थी। अर्थात पर खेतीबाड़ी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता व्यापार को दूसरे स्थान तथा नौकरी सबसे घटिया गिना जाता था। लेकिन उस्थितियां इसके विपरीत हैं। आज हर व सरकारी नौकरी पाना चाहता है। इससे सबसे बड़ा कारण यह रहा कि सरकारी में कर्मचारियों के वेतन में अत्यधिक बढ़ोतारी हुई है तथा सेवानिवृति के लिए पैशन की सुविधा होने से उनका भवित्व सुरक्षित हो जाता है। दूसरी ओर उशिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं की संख्या एकाएक वृद्धि हो रही है। ऐसे युवा सरकारी सेवा में नहीं जा सकते हैं, मजबूरी में कम वेतन पर निजी क्षेत्र में करते हैं। सरकारी एवं निजी क्षेत्र में सुविधा है कि हर महीने वेतन मिलता जबकि ग्रामीण क्षेत्र में फसल अच्छी होने बाद यदि उसका दाम ठीक मिले तो समझ जाता है कि कम से कम फसल पर जिल खर्च हुआ था, उसकी भरपाई हो गी। ग्रामीणों को दुधारू पशु या भेड़-बकरियों आदि के बिकने पर ही नकद पैसा प्राप्त होता है।



से पशुपालन का व्यवसाय भी नाममात्र का रह गया है। गांव में अब कोई विरला ही परिवार है, जिसने गाय या कोई भेड़-बकरी पाल रखी है। अन्य पशु अब लावारिस होकर सड़कों पर भटक रहे हैं। पहले शहर में ही इक्का-दुक्का लावारिस पशु नजर आते थे, लेकिन अब गांव-गांव तक लावारिस पशुओं के झुंड घूमते देखे जा सकते हैं। ग्रामीणों को लग रहा है कि अब खेतीबाड़ी एवं पशुपालन बहुत ही घाटे का सौदा हो गया है। इन दोनों व्यवसायों में खर्च के मुताबिक आय नहीं हो रही है। सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हलांकि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिए जाने के बाद कृषि क्षेत्र में मामूली सुधार हुआ है। लेकिन इसके लिए और अधिक धनराशि की जरूरत है। यदि सरकार बैल पालने के लिए हर महीने प्रति जोड़ी 1500, गाय या भैंस पालने के लिए 750 रुपए मासिक तथा भेड़ व बकरी पालन के लिए 250 रुपए अनुदान दे, तभी कृषि के साथ ही पशुपालन व्यवसाय पिर से पनप पाएगा। इससे एक तो बेसहारा पशुओं की समस्या का हल होगा तथा दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की तरह कृषि उपज भी बढ़ेगी। ग्रामीणों को अपने गांवों में अच्छा अनाज, शुद्ध दूध-दही व धी के साथ ही फल व सब्जियां उपलब्ध होंगी। ग्रामीणों को अपने घरों में ही रोजगार उपलब्ध होगा। इससे हिमाचल सरकार को दूध व प्रस्तावित गोबर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले करीब चार दशकों से न केवल आरोपी के बाने में जो विवर बढ़ोत्तरी हुई है तथा सेवानिवृत्ति के बैंशन की सुविधा होने से उनका भवित्व सुरक्षित हो जाता है। दूसरी ओर उशिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं की संख्या एकाएक वृद्धि हो रही है। ऐसे युवा सरकारी सेवा में नहीं जा सकते हैं, मजबूरी में कम वेतन पर निजी क्षेत्र में कारते हैं। सरकारी एवं निजी क्षेत्र में सुविधा है कि हर महीने वेतन मिलता जबकि ग्रामीण क्षेत्र में फसल अच्छी होने वाला यदि उसका दाम ठीक मिले तो समझाता है कि कम से कम फसल पर जिस खर्च हुआ था, उसकी भरपाई हो गई किसानों को दुधारू पशु या भेड़-बकरियां आदि के बिकने पर ही नकद पैसा मिलता है।

